

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं०-85 / 2022-23

सरकार

-बनाम-

रवि सिंह वगै०

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक -2933/अ० शा० दिनांक - 18.10.2022 के द्वारा वादी श्री रामनाथ राय पे०-भवसागर राय, सा०-नारायण थाना-तरैया जिला-छपरा (बिहार) वर्तमान जिला खनन पदाधिकारी, गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर गुमला थाना काण्ड सं०-191/2022 दिनांक-29.06.2022 धारा-379/414/34 भा० द० वि० 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं 7/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम-2017 के तहत जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या JH01AL - 5785, के मालिक रवि सिंह पे०-रंजीत सिंह सा०-बीर कुंवर कॉलोनी नियर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल गुमला थाना-गुमला जिला-गुमला एवं ट्रैक्टर निबंधन संख्या JH07G - 6078 के मालिक बलराम यादव पे०-सुकरा यादव सा०-दुन्दरीया थाना-गुमला जिला-गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादीगण के द्वारा लिखित बहस समर्पित किया गया है, परन्तु उत्तरवादीगण के द्वारा सुनवाई के दौरान अवैध रूप से खनिज का परिवहन करने से संबंधित कोई वैध कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहे।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि श्री रामनाथ राय पे०-भवसागर राय, सा०-नारायण थाना-तरैया जिला-छपरा (बिहार) वर्तमान जिला खनन पदाधिकारी, गुमला के कम्प्यूटरकृत आवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध अवैध रूप से खनिज का परिवहन करने का आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 (यथा) संशोधित) के नियम-4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा-4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम-7 एवं 13 के तहत मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या JH01AL - 5785 एवं ट्रैक्टर निबंधन संख्या JH07G - 6078 के विरुद्ध खनिज का अवैध रूप से परिवहन कर व्यवसाय करने के आरोप को सत्य पाया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:-

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer."

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing

seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं०-360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि "Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence, the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana"

अंकनीय है कि जप्त किये गये वाहनों को अवैध रूप से खनिज का भंडारित कर परिवहन कार्य किया जा रहा है। साथ ही इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नहीं रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नहीं होने के कारण उसको अवैध रूप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त खनिज एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों में उल्लिखित नियमों के विरुद्ध किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या JH01AL - 5785 एवं ट्रैक्टर निबंधन संख्या JH07G - 6078 को राजसात करता हूँ।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

19.12.21
उपायुक्त,
गुमला

19.12.21
उपायुक्त,
गुमला